

□□□□ □□□□

जनसत्ता 22 मई, 2014 : चुनाव प्रचार के दौरान वक्स के बहुतेरे मॉडल वभिन्न राजनीतिकदलों और उम्मीदवारों की ओर से प्रस्तुत की गी

इससे पहले के चुनावों में भी वक्स क कोई न कोई खाक पेश करके राजनीतिकदल मतदाताओं क विश्वास हासिल करते रहे हैं। इसके बावजूद ग्रामीण और दुर्गम पहाड़ी अंचलों में अधिकतर नागरिक आज भी स्वच्छ पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। लगता है वक्स क कोई भी मॉडल उनके कम नहीं आया है। या, वायदे करने वाले वायदों पर खरे नहीं उतरे हैं।

मशरति अर्थव्यवस्था पर आधारित नेहरू क वक्स मॉडल शुरुआती दौर में सार्थक साबित हुआ था। नब्बे के दशक तक आते-आते मशरति अर्थव्यवस्था विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के दबाव में मनमोहन सिंह की उदारवादी नीतियों क शक्ति हो गई। क्रीब के दशक तक इन नीतियों के चर्कित कर देने वाले परिणाम आते रहे। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति आई। परिवहन सुविधा उम्मीद से अधिक तेजी से वक्सित हुई। शहरीकरण और सेवा-क्षेत्र के वसितार ने बाकी सभी क्षेत्रों के बहुत पीछे छोड़ दिया। इस प्रगतिके देख कर योजनाकर और राजनेता दग्भ्रमति-से हो गे। और शायद प्रगतिके भूगोल के समझने में बहुत बड़ी चूक कर गे। नजीकरण की नीतियों ने अर्थव्यवस्था के नई दिशा देना शुरु कर दिया। समग्र और समन्वित वक्स के वायदे धीरे-धीरे पीछे छूटते चले गे, जो नेताओं ने मतदाताओं से की थे। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के संक्रमण-काल में बहुमूल्य दस-पंद्रह साल गुजर गे। और वर्ष 2014 के आम चुनाव ने दस्तक दे दी।

इस आम चुनाव क सबसे उल्लेखनीय पहलू यह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुदूर गांवों में उन उपेक्षित वर्गों की दहलीज पर भी पहुंचा है, जो भारतीय लोकतंत्र के वास्तविक प्रहरी हैं। और जनिके ली। चुनावी घोषणापत्र में कया गया क कवायदा मायने रखता है। मीडिया के कैमरे ने सब कुछ साफ-साफ दिखाया है। कतरफ बहुमंजिला वातानुकूलित आशयाने तो दूसरी तरफ घास-पूस की झोंप। थियों में जदिगी कट रहे लोग। कहीं कंक्रीट की चमकती स। केंतो कहीं पैदल चलने के ली। भी पगडंडियों के ढूं। ते नागरिक। वक्स की इस सीमति और अंधी दौ। में कछोटे-से वर्ग के जरूर फयदा मलिा है। पर आम नागरिक तथाकथित वक्स के इस दौर में लगातार पछि। ता चला गया है।

नजीकरण की अवधारणा ने बहुत थो। समय में ही यह साबित कर दिया है कि वह उपभोक्तावाद के ब। वा देकर अधिकतम लाभ अर्जति की परक्ल्पना मात्र है। नव-उदारवाद की नीतियों क ही प्रतफिल है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार ब। ती जा रही है। अधिकतर देशी और वदिशी पूंजी नविश अर्थव्यवस्था के उन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है जहां मुनाफे की गुंजाइश है। उदारवादी अर्थव्यवस्था सीमति मध्यवर्ग और उच्चवर्ग के ही पोषित करती नजर आ रही है। गरीब तबक अर्थव्यवस्था के दायरे से बाहर हो गया लगता है। ऐसे में उन्हें तरह-तरह के लॉलीपॉप देकर सरकरें अपने दायत्व नभिा देने क उपक्म करती नजर आ रही है।

शासन करने वाले राजनेताओं के यह पता है कि मुख्यतया नमिनवर्ग के वोट से सरकारें बनती आई हैं। इसलिये पछिले लगभग दो दशक में इस वर्ग के खुश रखने के लिये एक दूसरे प्रकार के मॉडल के आधार बना कर उन्हें वोट की राजनीति में प्रासंगिक रखने का प्रयास किया जा रहा है। यह सोच विकास की किसी भी मॉडल पर आधारित न होकर कल्याणकारी राज्य के दायित्वों का गुणगान करते हुए विकास किया गया है। जन-कल्याण के नाम पर नागरिकों के नटिल्ला बनाने और भ्रष्टाचार की मानसिकता से ग्रस्त करने का यह मॉडल वोट बटोरने के लिये सार्वजनिक हथियार बन सकता है, राष्ट्रीय विकास के लिये नहीं। लोगों के लगभग मुफ्त भोजन और घर के द्वार पर तथाकथित रोजगार देने की योजना इसी मॉडल का प्रतीक है।

वर्ष 2009 के आम चुनावों में इस प्रकार की योजनाओं का मतदाताओं पर राजनीतिक असर भी दिखाई दिया था। इसकी संभावना कम है कि यह मॉडल आगे भी सरकार साबित होगा। वर्तमान विकास की अवधारणा कल्याणकारी नीतियों की आगे में राजनीतिक मंतव्यों की दासी बन कर रह गई है। संरचनात्मक और ढांचागत विकास की योजना धन के अभाव में धीरे-धीरे विकास मॉडल से गायब हो चुकी है। ऐसे में नौकरशाही में भ्रष्टाचार और राजनीति में स्वार्थ का बोलबाला हो जाना स्वाभाविक है।

लोकलुभावन नारे, वायदे और योजना का कठ की हांडी की तरह होते हैं। कबार चल जाते हैं, पर बार-बार नहीं। वास्तविक विकास ही स्थायी राजनीतिक सुरक्षा का आधार बन सकता है। इस बार के आम चुनाव ने सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों को फिर से परखने और उन्हें पुनः निर्धारित करने का अवसर प्रदान किया है। शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव के प्रगतिक पैमाना मान लेने की भूल कर रहे अर्थशास्त्रियों की आंखें अब खुल जानी चाहिए। देश का समग्र और समन्वित विकास के मॉडल की प्रतीक्षा में है।

मूलभूत सुविधाओं के लिये बाट जोह रहा आम आदमी किसी भी सार्वजनिक आर्थिक विकास मॉडल के केंद्र-बिंदु में होना चाहिए। सरकार हर व्यक्ति के घर-घर जाकर विकास नहीं कर सकती। यह जरूरी है कि जन-जन को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाय, जो कति भी संभव है जब आम नागरिक की आमदनी बढ़े। उसे अर्थव्यवस्था की धुरी बनाया जाय। इसके लिये न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना और किसान की उपज का लाभकारी मूल्य निर्धारित करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है। बचौलियों के बीच से हटा कर कृषि उत्पादों के दाम न्यंत्रित की जा सकते हैं। कम करने वालों के लिये कम की कमी नहीं है, पर गैर-उत्पादक योजनाओं की समीक्षा करके खजाने के उत्पादनमुखी धंधों में लगाने की आवश्यकता है। गरीब की खरीद-कमता बढ़ाने से अर्थव्यवस्था का आधार व्यापक बनेगा और मंदी की मार झेल रहे बाजार स्वतः पटरी पर लौट आयेगे।

शहरीकरण में जिस प्रकार विकास हो रहा है उसमें सरकार की भागीदारी नगण्य है। पुरानी और मलिन बस्तियों को छोड़ कर, शहरी विकास प्रक्रिया में नज्दी क्षेत्र की भूमिका को और सशक्त बनाया जा सकता है। पुरानी बस्तियों को धीरे-धीरे नवीकरण का हिसा बना कर मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा सकता है।

जल प्रबंधन ऐसा विषय है जिसके माध्यम से ऊर्जा, पीने के पानी और सचिवाई के लिये पानी की व्यवस्था का साथ की जा सकती है। दुरभाग्यवश पछिले कई दशकों में इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। कहीं धन की कमी आती रही तो कहीं पर्यावरण संरक्षण के नाम का रोना। इन बाधाओं को दूर करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। नदियों को जोड़ने की अटलजी की योजना को जन-आंदोलन बनाने की आवश्यकता है।

हवाई जहाज की यात्रा सुलभ बनाने के लिये नज्दी क्षेत्र सदैव अग्रणी रहा है। इसलिये हर गांव-बस्ती को पक्की सड़क से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। परिवहन व्यवस्था किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रगतिके मूल्यांकन का प्रमुख आधार होती है। मट्टी के कर्मों में रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजनाओं में धन बहाने के बजाय पक्की सड़कें का ताना-बाना मजबूत बनाने की प्रयोजनाओं में रोजगार के अवसर पैदा की जा सकते हैं।

रेत, बजरी, केयला, सीमेंट और लोहे के भंडारों पर माफिया कुंठली मारे बैठा है। रही-सही कसर पर्यावरण संरक्षण के नाम पर उठाई जा रही आपत्तियों ने पूरी कर दी है। नरिमाण गतिविधियां ठप होकर रह गई हैं। माफिया पर अंकुश लगा कर और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के व्यावहारिक बना कर नरिमाण प्रक्रिया के गतिप्रदान करने की आवश्यकता है। इससे रोजगार के अवसर स्वतः ही उपलब्ध होंगे।

कल्याणकारी राज्य में लोगों के घरों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाना और घर-घर में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व होना चाहिए। इन कामों के लिए धन की कमी आ नहीं आनी चाहिए। ग्रामीण विकास की बाकी सभी परियोजनाएं पांच वर्ष और इंतजार कर सकती हैं।

उच्च शिक्षा के प्रसार में नज्दी क्षेत्र पहले ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शहरों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने की वर्तमान सुविधाएं संतोषजनक कही जा सकती हैं। पर ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाएं अब भी अपर्याप्त हैं। वहां न तो स्कूल भवन हैं और न ही शिक्षक। इस ओर प्राथमिकता के आधार पर काम करने की जरूरत है। लैपटॉप और टेबलेट बांटने वाली परियोजनाओं में धन की बर्बादी रोक कर हर गांव-बस्ती में जरूरत के अनुसार स्कूल खोल कर उनमें योग्य स्थानीय अध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य हासिल कर लेना कोई दुष्कर कार्य नहीं है।

उच्च और व्यावसायिक शिक्षा मुट्ठी भर लोगों के मुनाफा कमाने का जरिया बन गई है। इन संस्थानों में अध्यापन का स्तर अत्यंत नमिन है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन शिक्षण संस्थानों से ऐसे छात्र पास होकर निकल रहे हैं जिनमें किसी भी दृष्टि से स्नातक नहीं माना जा सकता। उच्च शिक्षा के स्तर के सुधारना सरकार के लिए कंगभीर चुनौती है। इसके लिए भ्रष्ट पर्यवेक्षण और निरीक्षण प्रणाली को बदल कर नया सोच विकसित करने की जरूरत है।

चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किसी भी विकासशील व्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिए। नज्दी अस्पतालों ने उच्च और उच्च-मध्यवर्ग की चिकित्सीय आवश्यकताओं के अनुरूप साधन उपलब्ध करा दिए हैं। पर आम लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का अत्यंत अभाव है। नब्बे प्रतिशत मरीजों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं होती। उनकी जरूरतों की पूर्ति के लिए मेडिकल शिक्षा और सुविधाओं के ताने-बाने के आवश्यकता के अनुरूप नया स्वरूप देने की जरूरत है।

लघु, मध्यम और भारी उद्योग में विदेशी और स्वदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकारी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाना होगा। व्यवसायियों और उद्योगपतियों के इंस्पेक्टरी राज और भय के वातावरण से मुक्ति दिलाने की जरूरत है। फजूल के आयात को नरिंत्रित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के उपाय की जाने चाहिए कि देश के संसाधन देश में ही रहें और परिष्कृत होकर ही विदेशी बाजार में पहुंचें।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सुधारने के लिए पांच वर्ष का कार्यकाल कम नहीं होता, पर यह कम इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले, वर्षों से स्थापित भ्रष्ट व्यवस्था ही अवरोध बन कर खड़ी होगी। जरूरत इस बात की है कि भ्रष्ट और गलत विकास अवधारणाओं की शक्ति नौकरशाही और व्यवस्था के ऊपर से नीचे तक ठीक किया जा। छोटे-छोटे लक्ष्य निर्धारित करके उनकी समयबद्ध समीक्षा की जा। और यह तभी संभव होगा, जब कर्मशील नेतृत्व सच्ची भावना से देश की बागडोर संभालेगा। वर्ष 2014 के चुनावी मंथन से आम आदमी इसी प्रकार के विकास की उम्मीद रखता है। वरना जता और अकर्मण्यता का हलाहल तो हर चुनाव के बाद जनता के हिससे में आ ही रहा है।

फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें- <https://www.facebook.com/Jansatta>

ट्विटर पेज पर फॉलो करने के लिए क्लिक करें- <https://twitter.com/Jansatta>